

बिहार सरकार
ग्रामीण विकास विभाग

पत्रांक:- 136926 ग्रा०वि०, पटना, दिनांक:- 31-01-13
ग्रा०वि० - 10/बजट-33/2012

प्रेषक,

अमृत लाल मीणा,
सचिव ।

सेवा में,

सभी जिला पदाधिकारी / सभी उप विकास आयुक्त ।

विषय:- वित्तीय वर्ष 2012-13 की समाप्ति से पूर्व ग्रामीण विकास विभाग मांग संख्या- 42 के अंतर्गत योजना / गैर योजना संबंधित सभी उप शीर्षों में आवश्यक व्यय सुनिश्चित किये जाने के संबंध में ।

महाशय,

आप अवगत है कि विभागीय मांग संख्या-42 के अंतर्गत विभिन्न उप शीर्षों (योजना / गैर योजना) में व्यय हेतु राशि आवंटित की गई है ताकि वर्ष के दौरान कभी भी राशि के अभाव में कोई आवश्यक कार्य बाधित न हो ।


इसके बावजूद यह देखा जाता है कि वित्तीय वर्ष के अंतिम (मार्च) में उपलब्ध राशि को येन-केन-प्रकारेण खर्च करने की प्रवृत्ति बढ़ती है और अनावश्यक/अनुपादक मदों में भी खर्च किया जाता है ।

उपर्युक्त को ध्यान में रखते हुए यह निर्देश दिया जाता है कि 15 फरवरी, 2013 तक सभी बकाये दायित्वों से संबंधित विपत्रों को पारित कराकर संबंधित कोषागार/उप कोषागार में अवश्य पारित करा लिया जाय । यहां यह भी उल्लेखनीय है कि गैर योजना मद में कार्यालय व्यय, वाहन का ईंधन एवं रख-रखाव, सामग्रियों की आपूर्ति, मशीन एवं उपस्कर आदि मद में व्यय पर वित्त विभाग द्वारा प्रायः एक सीमा तक व्यय करने की रोक किसी समय लगा दी जा सकती है ।

अतएव तृतीय अनुपूरक के माध्यम से उपबंधित राशि जो प्रायः मार्च के तृतीय सप्ताह में उपलब्ध करायी जाती है, उसे छोड़कर सभी प्रकार की उपबंधित राशि का व्यय 15 फरवरी, 2013 से पहले कर लिया जाना सुनिश्चित किया जाय । यदि राशि की निकासी नहीं होती है और लंबित दायित्व बना रहता है तो इसके लिए संबंधित पदाधिकारी जिम्मेवार होंगे ।

उक्त निदेश की प्रति अपने अधीनस्थ प्रखंड विकास पदाधिकारी सहित सभी संबंधितों को तुरंत उपलब्ध करा दी जाय ।

विश्वासभाजन


30.1.13

(अमृत लाल मीणा)

सचिव